

भारत में रोज़गार के रुझान

प्रलिस के लयः

[रोज़गार, राषटरीय नमुना सरवेक्षण कारयालय, प्रधानमंती मुदरा योजना, प्रमुख रोज़गार, गगि अरथवयवस्था, सटारट-अप इंडया योजना, समाइल, अनौपचारक कषेतर](#)

मेन्स के लयः

भारत में रोज़गार की चुनौतयाँ, भारत में बेरोज़गारी, सरकारी पहल, वृद्ध और वकिस

[स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस](#)

चरचा में कयाँ?

भारत में हाल के वर्षों में [रोज़गार](#) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2022-23 के बीच 80 मिलियन से अधिक अतरकित नौकरयाँ का सृजन हुआ है।

- इन रुझानों के तेज़ी से बढ़ने के कारणों और इसकी स्थरिता पर चरचा शुरू हो गई है।

रोज़गार वृद्धि में प्रमुख रुझान क्या हैं?

- ऐतहासक वकिस:** वर्ष 1983 से वर्ष 2023 तक [राषटरीय नमुना सरवेक्षण कारयालय \(NSSO\)](#) के आँकड़ों का उपयोग करते हुए वश्लेषण सभी उप-अवधयाँ में प्रमुख रोज़गार में लगातार वृद्धि को दर्शाता है।
- नरंतर वकिस:** प्रमुख रोज़गार, जो वर्ष के अधकानश समय कार्य करने वालों को मापता है, वर्ष 1983 के बाद से लगातार बढ़ा है।
 - प्रमुख रोज़गार से तात्पर्य वर्ष के अधकानश समय में की गई मुख्य व्यवसाय से है, जबकि सहायक रोज़गार आमतौर पर अंशकालक, कम अवधका और मुख्य व्यवसाय के अतरकित होता है।
 - वचाराधीन प्रत्येक उप-अवधयाँ में प्रमुख रोज़गार में वृद्धि देखी गई है, लेकिन इन अवधयाँ में बेरोज़गारी में वृद्धि होने का कोई उदाहरण नहीं है।
- उल्लेखनीय वृद्धि (2017-2023):** वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अवधयाँ में लगभग 80 मिलियन अतरकित नौकरयाँ के साथ रोज़गार में तीव्र वृद्धि देखी गई, जो 3.3% की वार्षक वृद्धि दर में परवरतन करती है।
- श्रम बाज़ार संकेतक:**
 - वर्ष 2000 के बाद से दीर्घकालक गरिवट के बावजूद, हाल के वर्षों में प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतकों जैसे [श्रम बल भागीदारी दर](#), [कार्यबल भागीदारी दर](#) और [बेरोज़गारी दर](#) में सुधार देखा गया है।
 - ये सुधार वश्लेषण रूप से [कोवडि-19 महामारी](#) से पूर्व और उसके दौरान, वश्लेषण रूप से आर्थक संकट की अवधयाँ में हुए।
- व्यापक आधार पर वृद्धि:** रोज़गार वृद्धि ग्रामीण और शहरी कषेत्रों में तथा वभिन्न उद्योगों (वनिर्माण, कृषि, निर्माण, सेवाएँ) में उचति रूप से वभाजति की गई है।
- महलाओं और बुजुर्गों के रोज़गार में वृद्धि:** महलाओं के लयि रोज़गार में वृद्धि सरवाधक रही है, जो 8% वार्षक से भी अधिक है।
 - 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के रोज़गार में वार्षक वृद्धि दर लगभग 4.5% रही।
 - इस प्रवृत्तक के कई कारण हैं, जनिमें बढ़ता संकट, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों तक बेहतर पहुँच एवं देखभाल से संबंधति कारयाँ में अधिक लचीलापन शामिल हैं।
 - 1980 के दशक से, बुजुर्ग श्रमकियों की संख्या में वृद्धि हुई है; यह प्रवृत्तक लंबे जीवनकाल से संबंधति हो सकती है।
- रोज़गार स्थति सूचकांक:**
 - रोज़गार स्थति सूचकांक सात श्रम बाज़ार परणाम संकेतकों पर आधारति है, जसिमें नयिमति औपचारक कार्य में श्रमकियों का प्रतशित, आकस्मक मज़दूर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्व-रोज़गार श्रमक, कार्य भागीदारी दर, आकस्मक मज़दूरों की औसत मासक कमाई, शकषति युवाओं की बेरोज़गारी दर के साथ-साथ वे युवा भी शामिल हैं जो रोज़गार व शकषा या प्रशकषण में सलग्न नहीं हैं।
 - वर्ष 2004-05 और वर्ष 2021-22 के बीच ["रोज़गार स्थति सूचकांक"](#) में सुधार हुआ है।

- हालाँकि, इस दौरान कुछ राज्य (बिहार, ओडिशा, झारखंड, यू.पी.) सबसे नचिले पायदान पर रहे।
- अन्य राज्य (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात) शीर्ष पर बने हुए हैं।

रोज़गार गुणवत्ता कैसे वकिसति हुई है?

- **अनौपचारिक रोज़गार में वृद्धि:**
 - औपचारिक क्षेत्र में लगभग 50% नौकरियाँ **अनौपचारिक** हैं।
 - लगभग **82%** कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में नयोजित है।
 - लगभग 90% लोग अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं।
- **स्व-रोज़गार का प्रभुत्व:**
 - रोज़गार वृद्धि (44 मिलियन) के एक बड़े भाग के रूप में स्व-रोज़गार प्राप्त करने वाले श्रमिक और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक शामिल हैं।
 - यह **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana- PMMY)** जैसी सरकारी योजनाओं का परिणाम हो सकता है, जिसने इस क्षेत्र को आवश्यक धन उपलब्ध कराया है।
 - रोज़गार का प्राथमिक स्रोत **स्व-रोज़गार** है, जिसका रोज़गार के संबंध में वर्ष 2022 में 55.8% का योगदान था।
 - आकस्मिक रोज़गार (आवश्यकतानुसार कार्य के आधार पर कर्मचारियों को नयुक्त करना) 22.7% है और नियमित रोज़गार 21.5% है।

मज़दूरी और वेतन की प्रवृत्तियाँ हैं?

- हाल के वर्षों में कुल **मज़दूरी** और वेतन में सापेक्षिक स्थिरता देखी गई है।
- वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक वेतन और मज़दूरी की औसत वार्षिक वृद्धिनामात्र के संदर्भ में **6.6%** थी, लेकिन **मुद्रासफीती** के हिसाब से केवल **1.2%** थी।
- हालाँकि मज़दूरी के संबंध में स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के संकट की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है लेकिन जीवन यापन की स्थिति में भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।
 - संभावित कारणों में श्रमिकों की बड़ी आबादी और स्थिर श्रम उत्पादकता के कारण मज़दूरी/पारिश्रमिक में कमी शामिल है।

युवा रोज़गार की स्थितियाँ हैं?

- वर्ष 2000 से 2019 के बीच **युवा रोज़गार** और अल्परोज़गार में वृद्धि हुई लेकिन महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गतिवट दर्ज़ की गई।
 - हालाँकि समय के साथ युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच बेरोज़गारी के स्तर में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2022 में कुल बेरोज़गार लोगों में बेरोज़गार युवाओं की हस्तिसेदारी 82.9% थी और सभी बेरोज़गार लोगों में शक्ति युवाओं की हस्तिसेदारी वर्ष 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई।
- शक्ति युवाओं में बेरोज़गारी दर माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं से छह गुना अधिक (18.4%) और वर्ष 2022 में अशक्ति व्यक्तियों (3.4%) की तुलना में स्नातकों (29.1%) के लिये नौ गुना अधिक थी।
 - यह पुरुषों (17.5%) की तुलना में शक्ति युवा महिलाओं (21.4%) में अधिक था, विशेष रूप से पुरुष स्नातकों (26.4%) की तुलना में महिला स्नातकों (34.5%) में अधिक था।

भारत में रोज़गार संबंधित क्या चर्चाएँ हैं?

- **अनौपचारिक क्षेत्र का विकास:** जबकि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो कई नए अनौपचारिक रोज़गार उत्पन्न होते हैं, जिनमें सुरक्षा, लाभ या न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने का अभाव होता है।
- **युवाओं के लिये रोज़गार की गुणवत्ता:** हालाँकि, बेरोज़गारी दर अधिक नहीं है, लेकिन युवाओं के लिये रोज़गार का अक्सर नमिन् गुणवत्ता का होता है।
 - इसका अर्थ यह है कि युवा लोग उपलब्ध रोज़गार के लिये अतिशक्ति हो सकते हैं या स्वयं को **गगि इकाँनमी** जैसी अनश्चित स्थितियों में संलग्न पा सकते हैं।
 - गगि या प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिये चुनौतियों में रोज़गार सुरक्षा की कमी, अनयिमति वेतन और अनश्चित रोज़गार की स्थिति शामिल हैं।
- **जेंडर गैप:** कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है। कई महिलाएँ औपचारिक रोज़गार के स्थान पर अवैतनिक पारिवारिक कामकाज़ या अल्प वेतन वाले स्व-रोज़गार में संलग्न हो जाती हैं।
- **बेमेल कौशल (Skill Mismatch):** शिक्षा प्रणाली वर्तमान रोज़गार बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती है।
- **औपचारिकीकरण संबंधी चुनौतियाँ:** भारतीय कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत रहता है।
 - इसका अर्थ सरकार के लिये नमिन् कर राजस्व और श्रमिकों के लिये सीमिति सामाजिक सुरक्षा लाभ है।
- **रोज़गार स्वचालन:** कई देशों की तरह, स्वचालन भारत में कुछ क्षेत्रों के लिये संकट बन सकता है। इससे वनिरिमाण जैसे उद्योगों में रोज़गार वसिथापन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
 - **कृत्रमि बुद्धिमत्ता (AI)** के बढ़ने से रोज़गार प्रभावित हो सकता है, विशेषकर भारत के आउटसोर्सिंग उद्योगों में, जहाँ कुछ बैक-ऑफिस कार्य AI द्वारा किये जा सकते हैं।

- **आर्थिक संघर्ष के प्रती संवेदनशीलता:** अधिकांश कार्यबल अनौपचारिक या आकस्मिक रोज़गार पर निर्भर करते हैं। यह उन्हें आर्थिक मंदी या बाह्य संघर्ष के प्रती अत्यधिक संवेदनशील बनाता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया।
- **सरकारी नौकरियों की मांग में वृद्धि:** नज़ी क्षेत्र में रोज़गार सृजन की कमी के कारण सरकारी नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है।
 - यह स्थिति सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थिर रोज़गार की अपील को रेखांकित करती है।

रोज़गार संबंधी सरकार की पहलें:

- **आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन (SMILE)।**
- **PM-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हतिग्राही)।**
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।**
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।**
- **स्टार्ट-अप इंडिया योजना।**
- **रोज़गार मेला।**
- **इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना- राजस्थान।**
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना।**
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।**

आगे की राह

- **औपचारिकता को बढ़ावा देना:** पेरू की राष्ट्रीय रणनीति से सीख लेते हुए, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मियों को औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये रणनीतियों को लागू करना।
 - औपचारिकता में परिवर्तन के लिये पेरू के नीति रूपरेखा (FSP) एवं व्यापार और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NBA व NAP) में वर्किकृत दृष्टिकोण में हतिधारकों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य, व्यवसाय, शिक्षा, श्रमिक, नागरिक समाज तथा स्वदेशी लोग शामिल हैं।
 - अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यवसायों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिये। यह उन्हें औपचारिक बनाने के लिये प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाता है।
- **सीमांत समूहों के लिये लक्षित कार्यक्रम:** SMILE पहल के समान, सीमांत समुदायों के व्यक्तियों के लिये लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम लागू किये जाएँ।
- इस से समुदायों के मध्य समावेशिता सुनिश्चित होती है जो इन समुदायों को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये सशक्त बनाती है।
- **AI और ऑटोमेशन रीस्कलिगि:** AI, रोबोटिक्स एवं डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके ऑटोमेशन (स्वचालन) रीस्कलिगि के लिये कार्यबल तैयार किया जाए।
 - यह श्रमिकों को उभरते कार्य क्षेत्रों में अनुकूलन तथा योगदान करने की अनुमति देता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संवहनीयता:** एक संवहनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार की जाए जो गंगि श्रमिकों तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण करने वाले श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।
- **उद्यमिता और नवाचार:** उद्योग-वशिष्ट स्टार्टअप इनक्यूबेटर तथा एक्सेलेरेटर स्थापित किये जाएँ।
 - एंजेल नविशकों द्वारा नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जो स्टार्टअप के लिये प्रारंभिक चरण का नविश प्रदान करते हैं।
- **दूरस्थ कार्य अवसर:** कंपनियों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा दूरस्थ कार्य अवसर प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इससे प्रमुख शहरों से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिये नौकरी के अवसरों का वसितार होता है तथा बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि मनेस प्रश्न:

प्रश्न. अनौपचारिकरोज़गार वृद्धि, स्थिरता एवं सामाजिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? क्या औपचारिकीकरण और AI रीस्कलिगि को बढ़ावा देने से स्थायी रोज़गार सुनिश्चित हो सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016)

- लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- नरिधन कृषकों को वशिष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना
- वृद्ध एवं नसिसहाय लोगों को पेंशन प्रदान करना
- कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का नधियन करना

उत्तर: (a)

प्रश्न. प्रचलन बेरोज़गारी का सामान्यतः अर्थ है कि: (2013)

- (a) लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं
- (b) वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं है
- (c) श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है
- (d) श्रमिकों की उत्पादकता नीची है

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न: भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/employment-trends-in-india>

